

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :-प. 2(3)साप्र/2/2024- 03357

जयपुर, दिनांक : 15-10-2024

—: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की ऑनलाईन वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	आवंटी नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति	आवंटित राजकीय आवास
1.	385	Mrs PARINEETA SRIVASTAVA (Assistant Commissioner, FD(Admin))	31-Dec-2029	II-24 Gandhi Nagar
2.	386	Mr. Anand Kumar Gupta (Assistant Secretary, CMO)	31-Oct-2033	II-38 Gandhi Nagar
3.	387	Mrs SANTOSH GHODELA (Assistant Secretary To Government, GAD)	30-Nov-2034	II-46 Gandhi Nagar
4.	388	Mr. MADAN LAL MEGHWAL (Assistant Secretary To Government, GAD)	31-Jul-2033	M-5 Gandhi Nagar
5.	389	Mr. HARPHOOL SINGH KANWA (Assistant Secretary, FD(Admin))	30-Jun-2033	M-6 Gandhi Nagar
6.	390	Mr. MADAN LAL (Joint Director, Agr D)	31-Jul-2027	N-14 Gandhi Nagar
7.	391	Mr. Himanshu Meena (Analyst Cum Programmer (Dy. Director), IT&C)	30-Apr-2048	N-18 Gandhi Nagar
8.	392	Mr. ABHISHEK LAMBA (Accounts Officer, Statistics)	31-Jul-2049	N-24 Gandhi Nagar
9.	394	Mr. Mukesh H Mulani (Analyst Cum Programmer (Dy. Director), PGRD)	31-Mar-2049	M-12 Gandhi Nagar
10.	396	Ms. PRATIBHA VERMA (Chief Executive Officer, RD)	31-May-2054	305 Model Town

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।



2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।
9. क्रम संख्या 10 के आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1)/(क-4/2) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
11. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आवंटियों मेंसे यदि किसी आवंटी को अस्थायी राजकीय आवास आवंटित हैं तो उन्हें उक्त आवंटित आवास का कब्जे लेने हेतु निर्देशित कर अस्थायी आवास रिक्त कराया जाना सुनिश्चित करे।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय/द्वितीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही ऑनलाईन राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करे।
14. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/हीराबाग जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर/हीराबाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिकारीगण को ऑनलाईन राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करे।
17. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय/द्वितीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही ऑनलाईन राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करे।
18. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव